मध्य प्रदेश एक आदिवासी और अविकसित जिला है । मध्य प्रदेश में ऐसे किसान हैं जिनके पास आमदनी के दूसरे स्रोत नहीं हैं । मध्य प्रदेश गरीब लोगों का जिला है। वहां बाढ़ से लोगों को हानि हुई है । खरीफ की फसल पूरी तरह बरबाद हो गई है । जो धान की खेती करते थे, वे धान लगा नहीं पाए हैं । जो उसका रोपा लगाते थे, वह रोपा भी पानी के अंदर आ कर सड़ गया है । जो उसे सूखे तरीके से लगाते थे, वह उसे बो नहीं पाए हैं और जो उसमें अंकुर लगा कर धान की खेती करते मैं, वह भी नहीं हुई है । इसी तरह से सोयाबीन की बहुत बड़ी खेती होती थी, वह भी बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है । मक्के की खेती, ज्वार की खेती और छोटे अनाजों की खेती भी इसी तरह से प्रभावित हुई है । पूरी खरीफ की फसलें बहुत नगण्य हो गई हैं और फसल बोई भी नहीं जा सकी है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए, मध्य प्रदेश में आदिवासी संख्या के बाहुल्य को देखते हुए जो बाढ़ ने भीषण हानि की है, जनहानि की है, खेती की हानि की है, पशु-धन की हानि की है, उसे देखते हुए केन्द्र सरकार की तरफ से हमको और अधिक मदद दी जानी चाहिए विशेषकर छत्तीसगढ़ और मालवा जिलों के लिए शीघ्र ही और अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है । धन्यवाद ।

**श्रीमती वीणा वर्मा** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुए यह कहूंगी कि बहुत बड़े रूप में मध्य प्रदेश में बरसात से क्षति हुई है और खास तौर से छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा क्षति हुई है । मध्य प्रदेश की मांग जो है वह दो सौ करोड़ रुपए की है । अभी क्षणिक मांग दो सौ करोड़ की है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए सड़कें बनाने पर भी पहल की जाए क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा टूट गई हैं । छोटेछोटे डैम सब टूट गए हैं तो इस पर अत्यधिक आवश्यकता से और शीघ्रता से ध्यान दिया जाए और उस मांग को पूरा किया जाए ।

**उपसभापति** : श्री सतीश प्रधान, अभी तो कोरम बराबर है जब आप बोल रहे हैं ।

**Need to withdraw the Central Government Public Health Department's circular affecting probable HIV cases**

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Madam, very recently, I visited one of the blood-donation camps. While discussing with the Karyakartas in this field, I received a very disturbing news regarding the Central Government Public Health Department's confidential circular. The circular says that if somebody's blood is found at the time of testing to be HIV positive, the blood should be destroyed and that it is not to be revealed to the concerned HIV positive person. When I enquired about the reasons, I was told that the concerned person's or patient's life should not be ruined by informing him/her about it. Thereafter,

I discussed the said matter with many Government officials and doctors including private doctors. Whatever information I have received, I would like to put the same on record for the information of the House and for necessary action and I also expect the hon. Minister of Health and Family Welfare to come before the House and make a statement in this regard.

Madam, normally, blood is collected by two systems, one is from voluntary blood donors by holding blood donation camps and the other is from professional blood donors. The blood is collected at different places, namely, at Government or municipal hospitals, at blood donation camps, at private blood banks and also at institutions like Red Cross, etc. The Government has imposed a rule that samples of blood must go to the blood testing centres, which are very limited, at the district level only. I cannot understand the mind of the Government and in what

way the new rules are going to solve the problems of testing being faced by the people in the villages and other towns who need blood in case of an emergency.

I will now come back to the testing laboratories. The capacity of a laboratory is absolutely inadequate compared to the requirements of the area. We have made the facilities available for testing which are known as Elisa tests. But these tests are not foolproof or correct tests. Many times, these tests give different results. If somebody is found HIV-positive at the first test, a second sample must be taken for further investigation. Unfortunately, this practice is not being adopted.

Therefore, through you, Madam, I request the hon. Health Minister to make a statement on this issue and to assure the House that he will withdraw the circular, which is a dangerous one because if it is not informed to the person who is found HIV-positive, he may create problems for others.

Thank you, Madam.

---

## *GOVERNMENT MOTION*

**On the twenty-eighth and twenty-ninth reports of the former Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Fifth, Sixth, Seventh and Eighth reports of the National Commission for Scheduled Castes, and Scheduled Tribes** (Cont'd)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now continue the discussion on the SC/ST Reports.

मीणा जी, अब आप अपने भाषण को कनक्लूड कर दीजिये तो मैं मंत्री जी से कहूं कि वह जवाब दें Every body is awaiting Ministers' reply. तो जो लोग हैं नहीं, उनको आप छोड़िए। मेरे कहने का मकसद यह था कि इस पर आप बोलें, और भी लोग बोलें, कटारिया जी कुछ बोलना चाहें तो बोलें मगर सवाल यह है कि मंत्री जी जो बोलेंगे, वह ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप सब लोग तो एक ही बात कहेंगे ।

**श्री मूलचन्द मीणा** (राजस्थान) : मैडम, यह शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का सौभाग्य है कि इतना टाइम मिला है।

**उपसभापति** । इसीलिए मंत्री जी क्या आपके सवालों का जवाब दें और क्या प्रोपोजल्स दें, मुझे लगता है कि वह जरूरी है इसलिए आप संक्षेप में अपना भाषण कनक्लूड कीजिए ।

**श्री मूलचन्द मीणा** : मैडम, कल मैं यह कह रहा था कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावनाओं के अनुसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अन्दर व्यवस्था की है । नेहरू जी ने जो अर्थव्यवस्था की, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया और अर्थव्यवस्था को मिक्स किया जिससे गरीब तबके के लोगों को उसका लाभ मिल सके । मैं कह रहा था कि इंदिरा जी ने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। इसके माध्यम से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिल सका और उनका विकास हो सका । इस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीनें भी मिलीं, बजर भूमि का अलॉटमेंट भी शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के नाम हुआ । साथ ही इंदिरा जी ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले वर्गों के लिए भी बकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे इन वर्गों के लोगों को बैंकों से ऋण लेने में सुविधाएं मिलीं । हम यह कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी जी ने शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ लागू किया । आज की जो सरकार है, उसने जो कार्यक्रम दिये हैं शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए, इनको हम नकार नहीं सकते । कहने के लिए यह कहा जाता है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ किया नहीं